

विकास हेतु वित्तीय समावेशन की एक सशक्त क्षेत्रीय वाहक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

अजय कुमार

सहायक प्राचार्य

अर्थशास्त्र विभाग

बी.एस.एस. कॉलेज, सुपौल

बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

सार

समावेशी विकास, विकास का ही एक रूप है जिसके तहत विकास प्रक्रिया में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वह व्यक्ति निरक्षर व सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जीवन क्यों ना व्यतीत कर रहा हो। इस प्रकार वित्तीय समावेशन से अभिप्राय उस समाज के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक मामलों में मुख्यधारा से जोड़ने से है। "वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा के पीछे जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह गांधीवादी दर्शन है "अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय - सबसे कमजोर व्यक्ति के उत्थान के माध्यम से सभी लोगों का कल्याण" में प्रतिध्वनित होता है। 'समावेशी' और 'समानता' के मूल उद्देश्य इस दर्शन के केंद्र में हैं जिसका दायरा गरीबी उन्मूलन से आगे तक जाता है। इसके दायरे में गरीबों, महिलाओं, किसानों, छोटे उद्यमों और अन्य लोगों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करना शामिल है। 1 समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन एक आवश्यकता होती है। इसके जरिये देश में विकास को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने, और टिकाऊ विकास हांसिल करने का मकसद होता है। इसके तहत कमजोर तबके और कम आय वाले लोगों को किफायती दर पर वित्तीय सेवाएँ और समय पर पर्याप्त कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। हमारा देश भारत विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है।

शब्द कुँजी :- समावेशी, 'समानता', वित्तीय समावेशन, उत्थान, टिकाऊ विकास, सुदूर ग्रामीण, सामाजिक सुरक्षा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार, बैंकिंग, ऋण सुविधाएँ, वित्तीय साक्षरता, डी. बी.टी

विकास से अभिप्राय सामान्यतया वस्तुस्थिति में समय के साथ पहले से बेहतर से होता है। परन्तु अर्थशास्त्र में विकासशील देश के सन्दर्भ में विकास से अभिप्राय देश बेहतर के लिए अप्रयुक्त संसाधनों तक पहुँच और उसके समुचित दोहन से लिया जाता है हमारे देश भारत में बहुत से संसाधन हैं जिसका भारत के विकास में योगदान या तो नगण्य है या बहुत कम है जैसे -और उर्जा, पवन उर्जा, बंजर भूमि, रेगिस्तान, मानव पूंजी जो बेरोजगार हैं आदि, और यही से जब अप्रयुक्त संसाधनों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने का और उसके समुचित दोहन की बात आती है तो समावेशन के विचार का जन्म होता है। इस प्रकार विकास हेतु समावेशन का स्वरूप बहुत वृहद हो जाता है। यहाँ समावेशन से अर्थ उत्पादन के संसाधनों के अलावा मानव संसाधनों का विकास प्रक्रिया में समावेशन से है और आज यह कई अवधारणाओं के रूप में परिलक्षित हो रहा है जैसे - सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, सुशासन, महिला सशक्तिकरण आदि।

समावेशी विकास, विकास का ही एक रूप है जिसके तहत विकास प्रक्रिया में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वह व्यक्ति निरक्षर व सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जीवन क्यों ना व्यतीत कर रहा हो। इस प्रकार वित्तीय समावेशन से अभिप्राय उस समाज के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक मामलों में मुख्यधारा से जोड़ने से है। "वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा के पीछे जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह गांधीवादी दर्शन है "अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय - सबसे कमजोर व्यक्ति के उत्थान के माध्यम से सभी लोगों का कल्याण" में प्रतिध्वनित होता है। 'समावेशी' और 'समानता' के मूल उद्देश्य इस दर्शन के केंद्र में हैं जिसका दायरा गरीबी उन्मूलन से आगे तक जाता है। इसके दायरे में गरीबों, महिलाओं, किसानों, छोटे उद्यमों और अन्य लोगों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करना शामिल है। 1 समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन एक आवश्यकता होती है। इसके जरिये देश में विकास को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने, और टिकाऊ विकास हांसिल करने का मकसद होता है। इसके तहत कमजोर तबके और कम आय वाले लोगों को किफायती दर पर वित्तीय सेवाएँ और समय पर पर्याप्त कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। हमारा देश भारत विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी भी देश को वित्तीय समावेशन के द्वारा समावेशी विकास एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। "सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र के न्यूयार्क शिखर सम्मेलन जो 25-27 सितम्बर 2015 को आयोजित हुआ, में लिया गया। इस सम्मलेन में वर्ष 2030 तक अर्थात् कुल 15 वर्षों में प्राप्त करने हेतु 'कुल 17 लक्ष्य' निर्धारित किये गए जो निम्न टेबल में दर्शाया गया है -

लक्ष्य	उद्देश्य	विवरण
लक्ष्य -1	गरीबी की पूर्णतः समाप्ति	दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना. अभी उन लोगों अत्यधिक गरीब माना जाता है जो कि प्रतिदिन \$ 1.25 से कम में जिंदगी गुजारते हैं.
लक्ष्य -2	भुखमरी की समाप्ति	भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा
लक्ष्य -3	अच्छा स्वास्थ्य और जीवनस्तर	सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवनस्तर में सुधार लाना.

लक्ष्य -4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	समावेशी और न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना.
लक्ष्य -5	लैंगिक समानता	लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना.
लक्ष्य -6	साफ पानी और स्वच्छता	सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना
लक्ष्य -7	सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा	सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना
लक्ष्य -8	अच्छा काम और आर्थिक विकास	निरंतर, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ, उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना
लक्ष्य -9	उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास	मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना.
लक्ष्य -10	असमानता में कमी	देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता कम करना
लक्ष्य -11	टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास	शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना
लक्ष्य -12	जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन	उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना
लक्ष्य -13	जलवायु परिवर्तन	जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना
लक्ष्य -14	पानी में जीवन	टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना
लक्ष्य -15	भूमि पर जीवन	सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना
लक्ष्य -16	शांति और न्याय के लिए संस्थान	टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना
लक्ष्य -17	लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी	सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना.

उपर्युक्त टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी) मानव जीवन के लगभग हर पहलू को कवर कर रहे हैं। यदि ये लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर हासिल किए जाते हैं, तो यह सुनिश्चित है कि दुनिया भर में गरीबों का जीवन आसान होना और उन्हें जीने के बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे।¹ 2 उपर्युक्त कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो बिना समावेशन के संभव हो। अतः समावेशन उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जहाँ एक अनिवार्यता है वहीं विकास को न्यायसंगत बनाने के लिये इसकी आवश्यकता है।

भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक जो भारत का केन्द्रीय बैंक है ने मिलकर बैंकिंग संस्थानों के सहयोग से अब तक वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत सारे कार्य किये हैं व कर रहे हैं। जिससे निम्न क्रियाएं सुनिश्चित हो रही हैं जो निम्न प्रकार हैं -

1. वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता सुगम बनाना - इसके जरिये लोगों को शिक्षा स्वस्थ कारोबार व परिसंपत्ति निर्माण में मदद मिलती है।
2. गरीबी और असमानता कम करने में मदद होना।
3. कर्ज की सुगम उपलब्धता, नवाचार, उद्योग के विकास में मददगार।
4. सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा, पेंशन सुनिश्चित करना।
5. पारदर्शिता सुनिश्चित होती है जिससे भ्रष्टाचार, कला धन पर विराम लगता है व संसाधनों पर आम आदमी को अधिकार मिलता है।
6. अस्थिरता और वित्तीय कमजोरी को दूर करता है व तरलता का समुचित प्रवाह सुनिश्चित करता है।
7. यह आम आदमी तक विभिन्न वित्तीय उत्पाद जैसे निवेश, बीमा, शेयर आदि की पहुँच सुनिश्चित करता है।

इन्हीं बैंकिंग संस्थानों में एक है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और हमारे अध्ययन का विषय -वस्तु है।¹ पवित्र नदी गंगा बिहार को दो क्षेत्रों, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। उत्तर बिहार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का घर है। सामेलन के पहले चरण में सात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात्: मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सीवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 1 मार्च से उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (यूबीकेजीबी) बनाने के लिए मिला दिया गया था।, 2006. सामेलन के दूसरे चरण में कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (KKGB) का 1 मई, 2008 को UBKGB में विलय हो गया और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (UBGB) का गठन हुआ। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है, और इसकी उपस्थिति अठारह जिलों में है; उत्तर बिहार के अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण और शिवहर। 1028 शाखाओं (636 ग्रामीण, 348 अर्ध शहरी और 44 शहरी शाखाएं) और 3340 बीसी आउटलेट (सुनहरा सपना केंद्र) का नेटवर्क अररिया, बेतिया, छपरा, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, झंझारपुर, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी और सीवान में 14 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।¹ 3 उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु कई कदम उठाये गए हैं जिसमें प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं -

1. जन - धन खाते / नो फ्रील खाते की सुविधा :- "प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई जिसका लक्ष्य निम्न है-
(a) बैंकिंग सुविधाओं तक सर्वजन पहुँच, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बेसिक बैंक खाता।
(b) वित्तीय साक्षरता, ऋण एवं बीमा तक पहुँच।

(c) लाभार्थी को एक रुपये डेबिट कार्ड जिसके अंतर्गत एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर |

(d) जो पहली बार बैंक खाता खोल रहे हैं 15 अगस्त 2014 तथा 26 जनवरी 2015 के बीच तथा जो योजना के लिए निश्चित अहर्ता पूरी करते हैं को 30000 रुपये का जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जायेगा | "4

उपर्युक्त लक्ष्यों के विरुद्ध प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत " SLBC(स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी) ने हमारे बैंक को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3673 उप-सेवा क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 89 वार्ड आवंटित किये हैं 31 दिसंबर, 2014 तक 5694072 (100%) परिवार उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से जुड़ चुके हैं।" 5

2. सेवाओं के सुपर्दगी हेतु शाखाओं का हर गाँव में प्रसार - उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक 1028 शाखाओं (636 ग्रामीण, 348 अर्ध शहरी और 44 शहरी शाखाएं) के साथ उपस्थित है।

3. बी. सी. मॉडल द्वारा सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुँचाने का प्रयास :- उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अपनी 3340 B.C. केन्द्रों (बैंक द्वारा इन्हे सुनहरा सपना केंद्र नाम दिया गया है) के माध्यम से उत्तर बिहार के 18 जिलों में कार्यरत है। वित्तीय समावेशन के लिए इसने ICT आधारित B.C.मॉडल को अपनाया है। जिसके द्वारा निम्न सुविधाएँ दरवाजे तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है -

a.) बचत खाते -ग्रामीण विकास खाता b.) स्मार्ट प्लेक्सी आरडी , बीसी के माध्यम से सावधि जमा उत्पाद।

c.) एनईएफटी के माध्यम से आवक विप्रेषण. d.) इन्टर- ऑपरेबिलिटी.

4. मोबाइल बैंकिंग / यू.पी .आई . / डेबिट कार्ड / एन .इ .एफ .टी / आर .टी .जी .एस . / समाशोधन आदि की सुविधा उपलब्ध करा कर नकद रहित विनिमय को बढ़ावा - उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक फ़िलहाल यू.पी .आई सुविधा को छोड़ सभी सेवा अपने ब्राह्मकों को शाखा व बी .सी . केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है।

5. विभिन्न प्रकार के ऋण सुविधाएँ - उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अपने क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण , संयुक्त देयता समूह (JLG)ऋण , स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋण , आदि के साथ विभिन्न मुद्रा ऋण , वाहन ऋण ,आवास ऋण , शिक्षा ऋण के साथ अपने क्षेत्र में उपलब्ध है और सेवा उपलब्ध करवा रही है |

6. डी. बी.टी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर):- इसके तहत जन धन योजना के माध्यम से खोले गए खाते मील का पत्थर साबित हो रहे हैं ,लाभुकों के खातों में सीधे कोष का हस्तांतरण कर लाभुकों को सीधा लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है व बिचोलियों की भूमिका इस मामले में लगभग शून्य हो गई है |

7. बीमा व सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन:- उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अपने ब्राह्मकों को शाखाओं व सुनहरा सपना केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न बीमा उत्पादों की सुपर्दगी कर रही है साथ ही भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना व अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है।

8. वित्तीय साक्षरता :-उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अपने 18 जिलों में 18 वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित कर व बी .सी . केन्द्रों (सुनहरा सपना केंद्र) के माध्यम से ग्रामीण व शहरी आबादी में वित्तीय उत्पादों की जानकारी प्रशारित कर निरक्षर व अब तक बैंकिंग सुविधा से वंचितों को जोड़ने का प्रयास कर रही है।

बेशक इन 18 जिलों में अन्य भी बैंक व उनकी शाखाएं हैं जो सामानांतर रूप से इस दिशा में कार्य कर रही हैं , परन्तु उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा इस दिशा में अन्य वाणिज्यिक बैंकों के अपेक्षा जिनके पास बेहतर आधारभूत संरचना व संसाधन क्षमता है किया जा रहा प्रयास प्रशंसनीय है | इस दिशा में और भी बेहतर किया जा सकता है यदि तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाये जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक आज भी यू .पी .आई . एवं नेट बैंकिंग की सुविधा अपने ब्राह्मकों को उपलब्ध नहीं करवा पाई है साथ ही वित्तीय साक्षरता अभियानों को ज्यादा आक्रामक करने की जरूरत है इसके तहत स्कूलों व कॉलेज को इस अभियान से जोड़ा जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :-

1. वित्तीय समावेशन - अतीत, वर्तमान और भविष्य* श्री शक्तिकांत दास www.rbi.gov.in
2. <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-all-the-sustainable-development-goals-in-hindi-1524127958-2>
3. <https://www.ubgb.in/history.aspx>
4. भारतीय अर्थव्यवस्था ,रमेश सिंह McGraw Hill Education(india)private limited 11वा संस्करण page-12.35
5. https://www.ubgb.in/hindi_aboutfi.aspx

